(d) what action has been taken in each case?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Allegations of irregularities as contained in the report are not tenable.

(d) Does not arise.

Setting up of gas based power plants

*5. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) what criteria have been fixed by Government for locating sites for setting up gas based thermal power plants in the country;

(b) whether the Punjab Government have also approached the Central Government for one such 400 MW power station; and

(c) if so, what action has been taken on the request?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) Proposals in respect of setting up of gas turbine power plants are examined keeping in view the availability of gas/fuel for power generation, the power requirements of the Region and other relevant techno-economic considerations.

(b) and (c) No project report has been received from the Punjab Government in regard to setting up of a 400 MW gas-based power station. The State Government have suggested extension of the HBJ pipeline to Punjab for supply of gas for power generation. The State authorities have been informed that, at present, further extension of the pipeline beyond Delhi does not appear to be feasible.

Details of STD calls in telephone bills

*6. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:

SHRI BHAGATRAM MANHAR:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in Bombay the details of STD calls made by subscribers are given in the telephone bills;

(b) if so, what are the reasons for not supplying such information to the subscribers in Delhi; and

(c) what steps are being taken to introduce this facility to the subscribers in Delhi also?

THE MINISTER OF ENERGY AND THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI VASANT SATHE): (a) Yes, Sir, the details of STD/ISD calls made from telephones connected to Electronic Digital Exchanges (E-10B) are supplied to those subscribers who opt for the same on payment of Rs. 25 in a bimonthly period alongwith their telephone bills.

(b) The above details are supplied to subscribers of E-10B exchanges in Delhi also who wish to have it on payment basis.

(c) Steps have been taken to procure equipment for this facility in strowger, crossbar and Electronic Analgo type of exchanges of Delhi.

उत्तर प्रदेश और हरियाणा में नई विद्युत परियोजनाएं

*7. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा इस समय उत्तर प्रदेश व हरियाणा में हाथ में ली गई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना के कब तक चालू हो जाने की संभावना है;

(ग) चालू योजना की अवधि के दौरान सरकार द्वारा किन-किन अन्य परियोजनाओं के हाथ में लिए जाने की आशा है;

(घ) निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने और पहले से ही स्वीकृत नई परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ करने के लिए राज्य सरकारों ने कितना अतिरिक्त सहायता किए जाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश और हरियाणा की स्वीकृति निर्माणाधीन विद्युत परियोजनायें तथा उनके चालू करने का कार्यक्रम निम्नानुसार है :—

परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	चालू करने का कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश		
टांडा	440	यूनिट–एक चालू कर दी गई है। यूनिट–दो, तीन तथा चार 1988–90 में चालू की जायेगी।
ऊंचाहार	420	1988–89
अनपारा "ख"	1000	1992–93, 1993–94
श्रीनगर	330	1994–95
लखवार व्यासी	420	1993–94, 1994–95
खारा	72	1991–92
विष्णु प्रयाग	480	नौवीं योजना
मनेरी भाली चरण—दो	304	नौवीं योजना
हरियाणा		
पानीपत चरण–तीन	210	1988–89
दादूपुर	10	1991–92
पश्चिमी यमुना नहर	4	1988–89

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश की लोहारी नागपाला, पालामनेरी, सोबला, राजघाट और ऊंचाहार परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दिया है, जिन्हें निवेश सम्बन्धी निर्णय लिये जाने के पश्चात् ही क्रियान्वयन के लिये हाथ में लिये जाने की सम्भावना है। हरियाणा की 420 मेगावाट क्षमता की यमुनानगर परियोजना को स्वीकृति दे दी गयी है।

ये राज्य क्षेत्र की परियोजनायें हैं तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों और योजना आयोग के परामर्श से अपेक्षित निधियां राज्य योजनाओं में उपलब्ध कराई जाती हैं। केन्द्रीय सहायता सामान्यतया एक ब्लाक के रूप में राज्यों को उपलब्ध कराई जाती है न कि किसी क्षेत्र/परियोजना के लिये।